IAS GS World PCS
Committed To Excellence
विशिष्ट संपादकीय सारांश
16 अगस्त 2024

अस्थिर हालात : घटता निर्यात

द हिन्दू
पेपर- III (अर्थव्यवस्था)

तीन महीने की वृद्धि के बाद, पिछले महीने भारत के माल निर्यात को झटका लगा। वर्ष 2023-24 के खराब प्रदर्शन के बाद, माल निर्यात में तीन महीनों की वृद्धि से हालात में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद जगी थी। जुलाई में मालों का लदान (शिपम.ेंट) 34 बिलियन अमेरिकी डॉलर से थोडा कम का रहा, जो 2023 के स्तर से 1.5 फीसदी की गिरावट को दर्शाता है। लेकिन यह नवंबर 2023 के बाद से सबसे कम आंकड़ा है और अक्टूबर 2022 के बाद से दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। भले ही भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 30 वस्तुओं में से 18 में वृद्धि दर्ज की गई, लेकिन बाकी वस्तुओं के निर्यात में उल्लेखनीय गिरावट आई है। बढ़ोतरी दर्ज करने वालों क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स (37.3 फीसदी ऊपर), रेडीमेड परिधान (11.8 फीसदी) और हस्तशिल्प (13.2 फीसदी) शामिल हैं। पेट्रोलियम पदार्थों के निर्यात में 22.2 फीसदी की गिरावट आई, जबकि रत्न एवं आभूषणों में 20.4 फीसदी तथा रसायनों में 12 फीसदी की गिरावट आई और कुछ खाद्य पदार्थों के निर्यात पर अंकुश से नुकसान जारी रहा। इसके साथ ही आयात खर्च में 7.5 फीसदी की ठोस वृद्धि हुई, जो पेट्रोलियम के आयात में 17.4 फीसदी की वृद्धि और उपभोक्ताओं की मांग से संचालित इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, दालें और वनस्पति तेल जैसे 'गैर-तेल, गैर-सोना' वस्तुओं के आयात में हुई उल्लेखनीय वृद्धि से प्रेरित रही। डॉलर के संदर्भ में सोने का आयात 10.7 फीसदी गिरा, लेकिन अप्रैल के बाद से यह तीन बि.लियन अमेरिकी डॉलर से लेकर 3.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच बना हुआ है। केंद्रीय बजट में आयात शुल्क में की गई कटौती के चलते, सोने का आयात और भी बढ़ सकता है। इसके अलावा, चांदी का आयात तेजी से बढ़ रहा है। मुख्य रूप से संयुक्त अरब अमी.रात के साथ व्यापार समझौते के तहत दी जाने वाली रियायती शुल्क की वजह से, जुलाई में चांदी का आयात लगभग 440 फीसदी बढ़ गया और यह 2024-25 के पहले चार महीनों में लगभग 202 फीसदी ज्यादा है।

बेशक, घटते निर्यात और बढ़ते आयात के चलते व्यापार घाटा लगभग 24 फीसदी बढ़कर 23.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया - जो नौ महीने का चरम है। व्यापार घाटे का और ज्यादा बढ़ने का जोखिम बना हुआ है, विशेष रूप से भारत के निर्यात

भारत के व्यापार घाटे के पीछे क्या कारण हैं?

1. **ऊर्जा आयात पर निर्भरता:** भारत अपनी कच्चे तेल की 85% से अधिक जरूरत को आयात करता है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक तेल कीमतों में उतार चढ़ाव के प्रति सुभेद्य हो जाती है, जिससे व्यापार घाटे पर काफी प्रभाव पड़ता है।
2. **प्रमुख इनपुट पर निर्भरता:** कुछ भारतीय उद्योग, जैसे फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंड.क्टर आदि आयातित कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुओं पर बहुत अधिक निर्भर हैं। इससे आयात मूल्य बढ़ता है और घाटा बढ़ता है।
3. उदाहरण के लिये, फार्मास्युटिकल क्षेत्र चीन से सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री का भारी मात्रा में आयात करता है।
4. **विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात में कमी:** चीन व अमेरिका जैसे देशों की तुलना में अल्प विनिर्माण क्षमता और वैश्विक बाजार में अल्प प्रतिस्पर्द्धात्मकता जैसे कारकों के कारण भारत से निर्यातित निर्मित वस्तुओं की मात्रा अक्सर आयातित वस्तुओं की मात्रा से अपेक्षाकृत कम रह जाती है।

व्यापार घाटे को नियंत्रित करने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

1. व्यापार समझौते
2. निर्यात अवसंरचना में सुधार
3. आयात प्रतिस्थापन
4. आयात को तर्कसंगत बनाना
5. कार्यबल को कुशल बनाना
6. मुद्रा और ऋण स्तर का प्रभावी प्रबंधन

की वैश्विक मांग के सापेक्ष घरेलू मांग के बने रहने की उम्मीद है। वाणिज्य मंत्रालय अभी भी आशान्वित जान पड़ता है और यह मानता है कि सेवाओं के मजबूत निर्यात के मद्देनजर भारत पिछले साल के रिकॉर्ड निर्यात के आंकड़े को पार कर जाएगा। लेकिन यह अनुमान अनिश्चित है क्योंकि मौजूदा एवं ताजे भू-राजनैतिक व्यवधान (बांग्लादेश) बार-बार उभर रहे हैं और माल ढुलाई की लागत में बढ़ोतरी ने कुछ निर्यातों को अव्यवहारिक बना दिया है। जिन्सों की कीमतों में हालिया गिरावट अलग चिंता का सबब है, खासकर चीनी अर्थव्यवस्था में गिरावट के चलते। चीन के उत्पादकों को कीमतों में कटौती करके वैश्विक बाजारों को अपने सामानों से पाट देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वैश्विक व्यापार के 2023 के मुकाबले तेजी से बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन भारत को इसके साथ कदम मिलाने और किसी भी लाभ को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। जहां नए बाजारों तक पहुंचने के लिए केंद्र द्वारा उठाए गए कदम काबिलेतारीफ हैं, वहीं वैश्विक त्योहारी ऑर्डर के लिए बोली शुरू से पहले निर्यातकों को उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के वास्ते आधिकारिक योजनाओं के जरिए ज्यादा निश्चितता प्रदान करना बेहतर होगा। शुल्क छूट योजना, आरओडीटीईपी, को जहां सिर्फ 30 सितंबर तक ही बढ़ाया गया है, वहीं बड़ी कंपनियों के लिए ब्याज सब्सिडी योजना जून में समाप्त हो गई और छोटी कंपनियों के लिए यह इस महीने बंद हो गई। इन योजनाओं की निरंतरता और यहां तक कि उनके विस्तार के लिए अंतर-मंत्रालयी बातचीत में तेजी लाई जानी चाहिए ताकि निर्यातकों को आखिरी समय में पेश आने वाली दिक्कतों के बजाय उनकी नजर अपने परिचालन संबंधी गणित को पूरा करने के लिए अपेक्षाकृत लंबी समयसीमा में सिर्फ काम पर ही रहे।

प्रारंभिक परीक्षा के संभावित प्रश्न (Prelims Expected Question)

प्रश्न: भारत के हालिया माल निर्यात के आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. पेट्रोलियम पदार्थों के निर्यात में 22.2 फीसदी की गिरावट आई है।
2. भारत का व्यापार घाटा लगभग 24 फीसदी बढ़कर 23.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

Que. Consider the following statements with reference to India's recent merchandise export data:

1. There has been a decline of 22.2 percent in the export of petroleum products.
2. India's trade deficit has increased by about 24 percent to US $ 23.5 billion.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2
(c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

उत्तर : C

मुख्य परीक्षा के संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न: भारत के माल निर्यात में आई कमी के कारणों की चर्चा करें साथ ही इसके स्थाई समाधान के लिए आवश्यक कदमों का भी उल्लेख करें।

उत्तर का दृष्टिकोण :

- उत्तर के पहले भाग में भारत के माल निर्यात में आई कमी के कारणों की चर्चा करें।
- दूसरे भाग में इसके स्थाई समाधान के लिए आवश्यक कदमों की चर्चा कीजिए।
- अंत में आगे की राह देते हुए निष्कर्ष दें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।